# पाँचवा-स्तम्भ

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 25 , अंक 2/2024


# श्री राम लला मंदिर एक सभ्यतागत मील का पत्थर है और यह वैश्विक भलाई में योगदान देगा: नृपेंद्र मिश्रा

नई दिल्ली में 'कट्स' इंटरनेशनल की 40वीं वर्षगांठ के व्याख्यान की श्रृंखला के अन्तर्गत 12वें व्याख्यान में बोलते हुए प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने 'अयोध्या में श्री राम लला मंदिर से संदेश' विषय पर व्याख्यान दिया।

उन्होंने कहा कि श्री राम लला मंदिर के महत्व को सभ्यतागत संदर्भ में समझने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभ्यता के प्रतीक के रूप में श्री राम लला का उदय न केवल भारत के सभी समुदायों के लिए बल्कि दुनियाभर के लिए भी फायदेमंद होगा।

मिश्रा ने मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प विवरण के बारे में बताया, जिसमें आवश्यक मूलभूत मजबूती प्रदान करना, लोहे का उपयोग नहीं करना, विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग होना एवं उन पर की गई नक्काशी आदि जैसे पहलू शामिल हैं। श्री राम लला मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह बड़ी सावधानी पूर्वक स्वदेशी वास्तुशिल्प की तर्ज पर, कई भारतीय अनुसंधान संस्थानों के तकनीकी सहयोग से अगले एक हजार वर्षों के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल और भारत के पूर्व वाणिज्य सचिव, श्री तेजेंद्र खन्ना ने भी कहा कि भारत का उदय सभी के लिए कल्याणकारी है। भारत सांस्कृतिक जागृति के दौर से गुजर रहा है। यह हमारे समाज के साथ-साथ उन वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भी अच्छा है जो सर्वसम्मति-आधारित परोपकारी दृष्टिकोण की मांग करता है।

'कट्स' इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप महता ने इस अवसर पर'कट्स' की 40 साल की यात्रा और जमीनी स्तर से वैश्विक स्तर तक जुड़ाव एवं योगदान के बारे में बताया। इसी संदर्भ में, उन्होंने भारत के वाणिज्य सचिव के रूप में तेजेंद्र खन्ना के दूरदर्शी नेतृत्व को याद किया, जब उन्होंने 'कट्स' और अन्य भारतीय गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान करने और नीति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने हित के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर काम करते समय, हम भाईचारा, कर्तव्य चेतना, मूल्यआधारित जीवन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं भूले हैं।

महता ने यह भी बताया कि साल भर में, 'कट्स' दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर क्रमवार आयोजित कर रहा है, जिससे न केवल 'कट्स' ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न विचारक समूहों को एक मंच पर एकत्रित किया बल्कि सभी के विचारों को एक मंच पर साझा करने का मौका दिया। इसी तरह पूर्व में हुए एक कार्यक्रम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक डॉ. ओकोन्जो-इवेला ने 'कट्स' की प्रशंसा करते हुए कहा था कि 'एक विकासशील देश के नागरिक समाज संगठन के लिए इतने लंबे समय तक टिके रहना वास्तव में गर्व की बात है। मैं इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से 'कट्स' को बधाई देना चाहता हूं।'

कार्यक्रम में लक्ष्मी पुरी, सुजान चिनॉय, संजीव सान्याल, राज चेंगप्पा, दीदार सिंह, अशोक चावला, राजीव भाटिया और जनरल अरुण साहनी जैसे कई विचारक नेताओं और नीति निर्माताओं ने भाग लिया।

## इस अंक में...


- सबसे अधिक बेरोजगारी वाले शीर्ष 5 राज्यों .. 3
- भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख 6
- ग्रीन एनर्जी में क्षमता से आगे राजस्थान ...... 8
- देश में जल संकट का गंभीर खतरा .......... 9
- कब मिलेगा 'आधी आबादी' को पूरा हक ... 11

# छोटे उद्यमियों को दिया ई-कॉमर्स से जुड़ने का प्रशिक्षण

स्थानीय उत्पादों को ई-कॉमर्स बाजार से जोड़ने और अच्छी बिक्री के उद्देश्य से 'कट्स' मानव विकास केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा नाबार्ड के सहयोग से दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र में नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक वसुंधरा ने कहा कि यह प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, माइक्रो एंटरप्राइजेज और छोटे उद्यमियों की पहुंच ई-कॉमर्स बाजार तक बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर रूडसेट इंस्टिट्यूट के दिनेश तोमर ने कहा कि उत्पाद ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देते हुए अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर लाने की प्रतिस्पर्धा में निपुर्णता के साथ आगे बढ़कर एक अच्छे उद्यमी बने। 'कट्स' के गौरव चतुर्वेदी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया।

# विश्व स्वास्थ्य दिवस पर किसानों की बैठक आयोजित

बांसवाड़ा जिला स्थित तलवाड़ा ब्लॉक के बोदला गांव में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 'कट्स' मानव विकास केंद्र चित्तौड़गढ़ के तत्वावधान में किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों को रासायनिक खाद का उपयोग बंद करने और जैविक वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

बैठक में किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हुए रासायनिक खाद से मानव जाति को हो रहे कुप्रभावों की जानकारी दी गई। बैठक में 'कट्स' मानव विकास केंद्र के जिला परियोजना अधिकारी सुरेश मिश्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल, रणछोड़ पाटीदार, नाहर सिंह सहित 25 से भी ज्यादा किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को हिस्सा राशि प्रमाण-पत्र का वितरण किया गया।

# धरातल स्तर पर परोपकार को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक

'कट्स' द्वारा धरातल स्तर पर लोगों में परोपकार की भावना जागृत करने के मकसद से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। इन गतिविधियों में प्रारंभिक तौर पर धरातल से जुड़ी आवश्यकताओं और परोपकार के लिए स्थानीय स्तर पर प्रचलित परिदृश्य को जानने एवं खासतौर पर ऐसे लोगों की पहचान करना है जो इस कार्यक्रमों में कई महत्वपूर्ण तरीकों से अपनी सहभागिता दे सकते हैं।

प्रारम्भिक चरण के तहत 'कट्स' की टीम ने 15 एवं 16 मई 2024 को कोटा और बारां जिलों का दौरा किया, जिनमें तीन ग्रुप चर्चाएं और साक्षात्कार सत्र आयोजित किए गए। इन साक्षात्कार सत्रों में स्थानीय परोपकार परिदृश्य से संबंधित कई मुद्दे और बहुमूल्य जानकारियां उभरकर सामने आई, जिनमें क्षेत्र विशेष के लिए परोपकार के तरीके और प्रेरणास्रोत शामिल थे।

इसी तरह, टीम ने 28 और 29 मई को जोधपुर का दौरा किया जहां पर ग्रुप चर्चाएं और साक्षात्कारों के माध्यम से स्थानीय हितधारकों से बातचीत की गई साथ ही स्थानीय परोपकार से संबंधित उल्लेखनीय मामलों की पहचान की गई, जो क्षेत्र में जमीनी स्तर से जुड़े प्रयासों और प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रारम्भिक गतिविधियों से प्राप्त विस्तृत जानकारी को रिपोर्ट में संकलित किया जा रहा है, जो कार्यक्रमों के अगले चरणों में अपनाई जाने वाली रणनीतियों में मार्गदर्शन करेगी।

## सबसे अधिक बेरोजगारी वाले शीर्ष 5 राज्यों में राजस्थान

देश में युवा सबसे ज्यादा रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही के लिए जारी सर्वे के मुताबिक देश में सभी आयुवर्ग के लोगों की बेरोजगारी दर जहां 6.7 फीसदी रही, वहीं 15 से 29 साल के बीच के युवाओं में बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत रही। यानी नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे हर 100 में से 17 युवाओं को काम नहीं मिला।

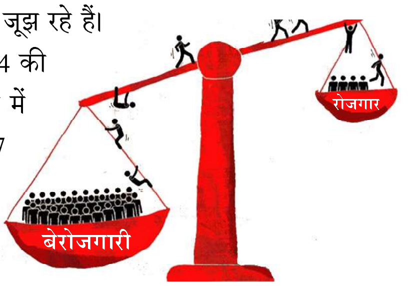


सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं (लड़के-लड़कियों) की सबसे कम बेरोजगारी वाले टॉप राज्यों में मध्यप्रदेश तो सबसे अधिक बेरोजगारी वाले शीर्ष 5 राज्यों में राजस्थान शामिल है। राजस्थान के युवाओं की बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि हर 100 में से 24 युवा काम की तलाश में हैं, पर उन्हें नौकरी या रोजगार नहीं मिल रहा। प्रदेश सरकार को रोजगार बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा।

*(रा.प., 25.05.24)*

### एनीमिया बिगाड़ रहा सेहत

प्रदेश में पोषण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा जिले में हालात चौंकाने वाले हैं। यहां पर डेढ़, दो व चार ग्राम हीमोग्लोबिन में सांसे चल रही है। बालिकाओं के साथ ही गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन का कम होना खतरनाक है।

यह ही नहीं यहां नवजात भी एनीमिया से अछूते नहीं हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती होने वाले नवजातों में हर पांचवा-छठा बच्चा सीवियर एनीमिक होता है। पड़ताल में सामने आया है कि जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों में हर पांचवा मरीज एनीमिक है। उपचार के लिए आने वाले मरीजों में 20 प्रतिशित एनीमिक होते हैं। इनमें 25 फीसदी सीवियर एनीमिक होते हैं। यह सब चिकित्सा विभाग की जानकारी में होते हुए भी सभी ने आंखें बंद कर रखी हैं।

*(रा.प., 05.04.24)*

### कौडियों के दाम पर बेच दी जमीन

जल संरक्षण विभाग के अफसरों ने भूमाफियाओं से मिलीभगत कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के लिए उद्यान विभाग की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम बेच डाली। जबकि इस जमीन पर जल संसाधन विभाग का कोई कब्जा ही नहीं था।

अफसरों की कारगुजारी उजागर होने पर सरकार तक बवाल मच गया। अब जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के बजाय गुपचुप नीलामी निरस्त करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार जल संसाधन विभाग ने उद्यान विभाग के बाड़ का बाग की करीब 7 बीघा जमीन को हरियाणा के एक भूमाफिया को करीब 3000 रुपए वर्गगज की दर से नीलाम कर दिया। जबकि इस जमीन की कीमत 15 से 18 हजार रुपए वर्गगज है। इस खेल में अलवर के भी तीन चार भूमाफिया शामिल बताए जा रहे हैं।

*(रा.प., 21.04.24)*

### सोशल मीडिया बना बेलगाम घोड़ा

सोशल मीडिया इन दिनों बिना लगाम के घोड़े जैसा हो गया है। प्रभावी नियंत्रण के बिना इस पर खुलेपन के नाम पर फूहड़त, बेशर्मी और अश्लीलता परोसी जा रही है। इससे पारिवारिक संस्कार दरक रहे हैं और बच्चों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। बच्चों और परिजनों के बीच संवाद कम हो रहा है। इसके कई घातक परिणाम सामने आ रहे हैं।

सर्वाधिक 97 फीसदी लोगों ने माना है कि सोशल मीडिया से अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है। यह राजस्थान पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से उजागर हुआ है। सर्वे में 93 फीसदी से ज्यादा लोगों ने माना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट देखी है। वहीं 98 फीसदी से भी ज्यादा लोगों का कहना है कि सोशल मीड़िया सामाजिक विकार दे रहा है और इसमें जरूरत से ज्यादा खुलापन आ रहा है। 93.7 फीसदी लोगों का मानना है कि सोशल मीड़िया पर सेंसर जरूरी है। *(रा.प., 12.06.24)*

### संकट में अरावली पर्वतमाला

अरावली पर्वतमाला अवैध खनन, ग्लोबल वार्मिंग व अतिक्रमण के चलते संकट में है। हाल ही स्वीडन के स्टॉकहोम में जलवायु परिवर्तन को लेकर आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस के पोस्टर सेशन में हुई चर्चा में यह सामने आया है कि अरावली में इसी तरह से खनन की गतिविधियां जारी रही तो राजस्थान का ग्रीन बैल्ट समाप्त हो जाएगा।

इस पर पैदा होने वाली वनस्पतियों से आयुर्वेदिक दवाएं बनती है। अब कई फलदार पेड़-पौधे और वनस्पतियां समाप्त हो गई है। इससे अरावली के तापमान में भी 2 से 5 डिग्री की वृद्धि हो गई। इन क्षेत्रों में पहले बड़ी संख्या में छोटे-बड़े प्राकृतिक झरने बहते थें। अब अरावली पर्वतमाला 50 प्रतिशत तक खोखली हो चुकी है और विनाश के करीब है। यही हाल रहा तो यूनिक ईको सिस्टम खत्म हो जाएगा और सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। यह एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है।

*(रा.प., 04.04.24 एवं दै.भा., 29.06.24)*

### गरीबों का हक डकार रहे कर्मचारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गरीबों का राशन डकार रहे 4,754 कर्मचारी पकड़े गए हैं। इन कर्मचारियों ने वर्ष 2018 से लेकर अब तक योजना का लाभ लिया था। प्रदेश सरकार ने जनाधार व आधार कार्ड से जांच की तो मामले का खुलासा हुआ।

पकड़े गए कर्मचारियों को योजना से बाहर कर इनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों से वसूली भी हो चुकी है और कुछ से की जा रही है। प्रशासन ने सभी एसडीएम को वसूली की जिम्मेदारी दी है। पता चला है कि कई अपात्र लोग भी योजना का फायदा ले रहे हैं। उनके राशन कार्ड भी फर्जी मिले हैं। गौरतलब है कि जिनकी आय 8000 रुपए मासिक है या सालाना एक लाख रुपए है उनको इस योजना से दूर रखा गया है।

*(रा.प., 06.05.24)*

## अस्पतालों में नहीं है जरूरी सुविधाएं

भारत में लगभग 80 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कर्मी, उपकरण और अन्य मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं।

स्वास्थ्य केंद्रों को सुविधाओं की संख्या जैसे विवरण 'ओपन डाटा किट' के जरिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड पोर्टल पर भरने के लिए कहा गया था। पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार एनएचएम 200988 स्वास्थ्य केंद्रों में से 43140 केंद्रों ने ही जानकारी उपलब्ध करवाई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 80 फीसदी स्वास्थ्य केंद्रों अर्थात 35051 के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वे इंडियन पब्लिक स्टैंडर्ड (आइपीएचएस) पर खरे उतरे। सरकार ने अब 100 दिनों में 70000 स्वास्थ्य केंद्रों को मानकों के अनुरूप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। *(रा.प., 30.06.24)*

## अटकी हुई है विद्या संबल योजना

राज्य सरकार ने कॉलेजों में विद्या संबल योजना के आदेश जारी कर प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग में अब तक यह योजना प्रारंभ नहीं हो पाई है। डेढ़ साल पहले नवंबर 2022 में शिक्षा विभाग में आवेदन लिए थे। लेकिन चयनितों की मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले ही इसको स्थगित कर दिया गया।

इसके बाद से आज तक योजना को शिक्षा विभाग ने शुरू ही नहीं किया। यह स्थिति तो तब है, जब शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 107947 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 83981 पद माध्यमिक शिक्षा में और 23966 पद प्रारंभिक शिक्षा में है। कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा विभाग की इस योजना में कई खामियां थी। इस कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष ईरा बोस का कहना है कि हम सरकार से जल्द भर्तियां शुरू करने और योजना को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। *(दै.भा., 29.06.24)*

## घोटाले की जांच ठण्डे बस्ते में

राज्य की पूर्ववर्ती सरकार में राष्ट्रीय आजीविका मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसकी जांच को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय चार मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया था। विधानसभा चुनाव आचार संहिता से पहले कमेटी की बैठक में बिना किसी निविदा प्रक्रिया अपनाए तथा आरटीपीपी नियमों की अनुपालना न करते हुए एकल स्त्रोत पर सीधे फर्म को कार्यादेश दिए जाने के मामले से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की अनुशंसा भी की गई थी। लेकिन बाद में इस मामले को कागजी खानापूर्ति कर दबा दिया गया। *(रा.प., 20.05.24)*

## बंटाईदारों के खातों में पड़ा सरकारी पैसा

सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक जैसलमेर में करीब 300 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए घोटाले के पैसे अभी भी फर्जी बंटाईदारों के खातों में सीज पड़े हैं। लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पिछले नौ महीने से अभी भी फाइलों में बंद है।

मामले के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बंदरबांट और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की मिलीभगत से किसानों के खेतों में फर्जी बंटाईदार डालकर फर्जी तरीके से 4800 से अधिक फर्जी बंटाईदारों ने करोड़ों रुपए का क्लेम डाल दिया। खेत के मालिकों को एक कौड़ी भी नहीं दी। मामले की जांच भी हो चुकी है और फलसूंड थाने में मामला दर्ज भी है लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। *(दै.भा., 14.06.24)*

## ओलावृष्टि मुआवजे में घपला

ओलावृष्टि पर मिलने वाले अनुदान में घोटाला सामने आया है। जोधपुर की कानासर जीएसएस (ग्राम सेवा सहकारी समिति) से जुड़े इस मामले में सरकार से मिले 91.42 लाख रुपए में से 89.54 लाख रुपए के गबन की आशंका जताई जा रही है।

एक परिवाद पर पड़ताल के बाद एसीबी ने इस परिवाद में कानासर जीएसएस के अध्यक्ष व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। वर्ष 2014-15 में हुई ओलावृष्टि पर सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी। इसके लिए कानासर जीएसएस को सरकार की ओर से अनुदान के रूप में 91.42 लाख रुपए मिले थे। मुआवजा वितरण में घपला कर जेल में बंदी और कई वर्ष पहले हुई मौत के किसानों को ओलावृष्टि का भुगतान किया जाना सामने आया है। *(रा.प., 03.05.24, 05.05.24)*

## खराब हवा ले रही लोगों की जान

भारत में वायु प्रदूषण हर घंटे 240 लोगों की जान ले रहा है, इनमें 20 बच्चे हैं। हाल ही यूनिसेफ व हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ ग्लोबल ऐयर 2024' ने इसे साबित कर दिया है। रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़े काफी चिंताजनक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लोग खराब हवा में सांस ले रहे हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में 2021 के आंकड़ों को लिया गया है, जिस वर्ष कोविड-19 के चलते रेल, सड़क और वायु ट्रैफिक अपेक्षाकृत कम था। रिपोर्ट कहती है वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से दुनिया में 81 लाख मौतें हुईं, इनमें से आधी मौतें चीन और भारत में हुईं। चीन में 23 लाख और भारत में 21 लाख लोगों की जान गई। वायु प्रदूषण से जान गंवाने वाले पांच वर्ष तक के बच्चों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा थी। *(रा.प., 20.06.24)*

## मिलीभगत से हो रहा फर्जीवाड़ा

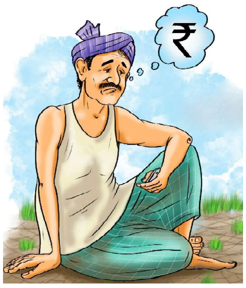


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रदेश के जालोर और सांचौर क्षेत्र में फर्जीवाड़ा करने वाले फर्जी आधार, शपथ पत्र बनवा, खुद ही बीमा किस्त जमा कराते हैं और बाद में उसका क्लेम भी उठा लेते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं।

जांच में सामने आया कि वहां जमीन मालिकों का अता-पता नहीं, मगर उनके नाम से बीमा क्लेम उठाया गया है। फर्जीवाड़े का यह खेल लंबे समय से चल रहा है। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि पर्यवेक्षक ऐसी जमीनें चिति करते हैं जिनका या तो वारिस नहीं होता या किसान प्रीमियम जमा कराने की स्थिति में नहीं होते। उन किसानों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को लीज पर दिखाया जाता है। वे ही राशि जमा कराते हैं और बीमा क्लेम पास होने के बाद राशि हड़प जाते हैं। अब तक करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। *(रा.प., 08.05.24)*

# सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

*हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।*

*गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।*

## जैव विविधता को होगा बड़ा नुकसान

सदी के मध्य तक जलवायु परिवर्तन जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण बन सकता है। इसका खुलासा एक नए अध्ययन में हुआ है। भूमि-उपयोग के तौर तरीकों में बदलाव और जैव विविधता पर उनके प्रभावों का अध्ययन करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया है कि दुनियाभर में जैव विविधता में 2 से 11 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

यह अध्ययन जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च (आइआइवी) के एक समूह ने किया है। अध्ययन के निष्कर्षों में सुझाव दिया गया है कि आवश्यक प्राकृतिक जलवायु समाधान के रूप में संरक्षण और बहाली के प्रयासों को विश्व स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शोधकर्ताओं ने आने वाले दशकों में नीतियों के बीच टकराव को कम करने व जैव विविधता की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थिरता पहलुओं पर विचार करते हुए समावेशी दृष्टिकोण का आह्वान किया है। जैसे जैव-ऊर्जा परिनियोजन जलवायु स्थिरीकरण परिदृश्यों का एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह प्रजातियों के घरों के लिए भी खतरा पैदा करता है। *(रा.प., 28.04.24)*

## स्टार्टअप भारत लौटने को बेताब

अधिक फंडिंग, बिजनेस ग्रोथ और टैक्स में मिलने वाली रियायत के लालच में बहुत सारे भारतीय स्टार्टअप्स ने अमरिका, सिंगापुर जैसे देशों में अपना बेस सेटअप कर लिया था, लेकिन एक-एक करके दर्जनों स्टार्टअप अब घर वापसी की तैयारी में जुट गए है।

हालांकि, विदेश से दोबारा भारत वापसी होने की प्रक्रिया काफी लंबी, जटिल और महंगी है इसके बावजूद पाइन लैब्स, ग्रो, मीशो, रेजरपे, जेप्टो , उड़ान जैसे दर्जनों स्टार्टअप स्वदेश लोटने को बेताब है। वेंचर कैपिटल फर्म्स व विशेषज्ञों का कहना है कि दोबारा अपना बेस भारत में स्थानान्तरित करना आसान नहीं है। घर वापसी के लिए इन कंपनियों को अमरीका जैसे देशों में भारी टैक्स चुकाना होगा। *(रा.प., 28.05.24)*

## प्रौद्योगिकी को बनाएं रचनात्मक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर देशों से कहा, प्रौद्योगिकी को रचनात्मक बनाएं, विनाशकारी नहीं। तभी हम समावेशी समाज की नींव रख पाएंगे। हमें मिलकर आने वाले समय को हरित युग बनाने का प्रयास  करना चाहिए। तभी हम तनावों और अनिश्चितताओं के दौर से उबर पाएंगे।

उन्होंने इटली के अपुलिया में हो रहे जी-7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह नसीहत दी। आज ग्लोबल साउथ के देश दुनिया भर में इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मोदी ने भारत में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर ठोस उपाय करने होंगे। सम्मेलन में जी-7 के सभी सदस्य देशों ने इस दशक में जीवाश्म ईंधन की कटौती पर तेजी से काम करने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। *(रा.प., 15.06.24)*

## प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कानून

दुनिया के 60 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे के लिए सिर्फ 12 देश जिम्मेदार है। इनमें भारत भी सम्मिलित है। हालांकि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में हम दुनिया में सबसे कम हैं। अनुमान है कि दुनिया में 2021 में 22 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ है। इसमें से 7 करोड़ टन पर्यावरण को प्रदूषित करेगा।

दुनिया में 60 प्रतिशत कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए चीन जिम्मेदार है। इसके बाद भारत, रूस, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की का नंबर आता है। भारत ने 2022 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट के नियमों के तहत 19 श्रेणी के सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया था। अब यूरोपियन यूनियन की ओर से मांग की गई है कि दुनिया के सभी देश इस श्रेणी के प्लास्टिक की पहचान करते हुए इसके निर्माण और उपयोग पर रोक लगाएं। *(दै.भा., 13.04.24 एवं रा.प. 22.04.24)*

## कम हुई असमानता की खाई

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के दौरान देश में आर्थिक असमानता में कमी आई है।

रिपोर्ट बताती है कि उपभोग पर खर्च में देश के सबसे अमीर 10 फीसदी परिवारों का हिस्सा कम हुआ और सबसे गरीब आदमी का खर्च बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के उपभोग व्यय में ग्रामीण व शहरी परिवारों के शीर्ष 10% का हिस्सा केवल 22.7% और 25.7% है। जबकि 2011-12 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए यह 24.6% और 29.7% था।

इस तरह सबसे अमीर आबादी के खर्च में 2011-12 की तुलना में कमी आई है। वहीं, कुल उपभोग में निचले 50% का हिस्सा 31.8% और 28.6% है। जबकि 2011-12 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निचले 50% का हिस्सा 30.9% और 25.9 था। इस तरह 2011-12 की तुलना में गरीब आबादी के खर्च में वृद्धि है। अमीरों की तुलना में गरीबों का उपभोग खर्च बढ़ना बताता है कि असमानता में कमी आई है। साथ ही, इससे यह भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में असमानता में ज्यादा कमी आई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता में अपेक्षाकृत कम कमी आई है। *(रा.प., 09.06.24)*

## बीमारियों की वजह है अनहेल्दी डाइट

देश में आधी से ज्यादा बीमारियों की खास वजह अनहेल्दी डाइट है। यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के इस्तेमाल के कारण बीमारियों का बोझ तेजी से बढ़ा है। देश में 56.4 फीसदी बीमारियां ऐसे ही खाद्य पदार्थों से हो रही है।

आईसीएमआर के अनुसार नमक चाहे काला हो, सैंधा हो या सफेद इनका ज्यादा इस्तेमाल नुकसान देता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि घी से बेहतर तेल का इस्तेमाल होता है। घी, पाम ऑयल और नारियल तेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं सरसों के तेल में सबसे कम पाए जाते हैं। भारतीय थाली में तीन तरह का फैटी एसिड व सैचुरेटेड फैट होता है। इस कारण दिल से जुड़ी बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। 56 प्रतिशत बीमारियां नूडल्स, चिप्स व आइसक्रीम जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से होती हैं। इसलिए इसे तत्काल कम करना चाहिए। *(दै.भा., 14.05.24)*

## ज्यादा कोल्डिंक्स पीना हानिकारक

देश में बिक रही कोल्डिंक्स में आईसीएमआर के मापदंडों से 5 गुना ज्यादा चीनी डाली जा रही है। इस ड्रिंक्स को बनाने में इस्तेमाल सामग्री और इसमें मौजूद कैलोरी भी छिपाई जा रही है। पड़ताल में पाया गया है कि इन ड्रिंक्स की बोतल में लोगो वाले लेबल के पीछे बहुत छोटी सी जगह में इन सामग्री या 'इंग्रेडिएंट्स' की जानकारी दी गई है।

कंपनियां अपने मूल देश अमेरिका में जो ड्रिंक्स बेचती है, उनमें लोगो वाले लेबल के नीचे एक और लेबल लगाया जाता है। जिनमें बड़े-बड़े अक्षरों में 'इंग्रेडिएंट्स' और कैलोरी की जानकारी लिखी रहती है। बड़ी कोल्डिंक्स कंपनियां रंगों की गुणवत्ता और केमिकल की जानकारियां भी छिपा रही है। आईसीएमआर के मुताबिक एक दिन में स्वस्थ व्यक्ति को 25 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए। अमेरिकन कार्बोनेट ड्रिंक्स में साफ लिखा रहता है कि इसमें कोई पोषण नहीं मिलता, यह कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है जबकि भारतीय कोल्डिंक्स में नहीं लिखा रहता। *(दै.भा., 17.06.24)*

## फूड पैकेट के फ्रंट पर हो चेतावनी

देश में ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अब बॉर्नवीटा जैसे उत्पाद हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से नहीं बेचे जा सकेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के नियमों और रेगुलेशन के तहत देश में हेल्थ ड्रिंक परिभाषित नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर जागरूकता लाने के लिए फूड पैकेट के फ्रंट पर चेतावनी आवश्यक है। पेय पदार्थों के बारे में भी नियम बनने चाहिए। किसी भी पेय पदार्थ में शुगर, सॉल्ट व फैट कंटेंट सबसे अहम होता है। इसकी मात्रा कितनी है यह लिखा होना आवश्यक है। विकसित देशों में फूड प्रोडक्ट के फ्रंट पर ही हेल्दी और अनहेल्दी लिखा होता है। इन पर वॉर्निंग लेबल भी लगा होता है। उपभोक्ता ये जानता है कि वह क्या खा रहा है और फूड प्रोडक्ट को खाने या पीने से उसे क्या नुकसान हो सकता है। *(दै.भा., 14.04.24)*

## आंखों में रंग झोंक रहे मिलावटखोर

प्रदेश की राजधानी में खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल जोरो पर चल रहा है। हाल ही मसालों में रंग और अखाद्य वस्तुओं की मिलावट सहित घी-तेल जैसी अन्य खाद्य सामग्रियों में कई तरह की मिलावट के मामले सामने आए हैं। वहीं, आम-चीकू-केला और पपीता जैसे फलों को खतरनाक केमिकल से पकाया जा रहा है।

यह सभी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा ऐसे मामले पकड़े भी जाते हैं लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं होने से इनका खामियाजा उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ता है। इनके सेवन से पाचन क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है। पेट में अल्सर और आंतों में सूजन आ सकती है। जी मिचलाना और पेट दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। चिकित्सकों का तो यहां तक मानना है कि कैंसर, दिमागी बुखार, नपुंसकता, हृदय रोग एलर्जी के साथ-साथ यह लोगों के लिए जानलेवा हो सकते हैं।

*(दै.भा., 21.05.24 एवं रा.प., 24.05.24)*

## मसाले अनसेफ, सेहत पर मुनाफा भारी

मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत देश के नामी मसाला कंपनियों के उत्पाद अनसेफ पाए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खिंवसर ने इन कंपनियों के विरुद्ध भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने और इन अनसेफ मसालों को तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि जांच में एमडीएच, एवरेस्ट, गजानन्द, श्याम, शीबा ताजा जैसी नामी कंपनियों के मसाले अनसेफ पाए गए हैं। इनमें तय मात्रा से अधिक पेस्टिसाइड मिला है। खाद्य सामग्रियों में अनसेफ श्रेणी को सेहत के लिहाज से घातक माना जाता है। इनका लगातार उपयोग किडनी, कैंसर जैसी घातक बीमारियां पनपाने के साथ जानलेवा भी हो सकता है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार, गुजरात व हरियाणा के अधिकारियों को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। *(रा.प., 08.06.24)*

## भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

सुप्रीम कोर्ट ने एफएमसीजी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीन मंत्रालयों से पूछा है कि वे इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में बताएं। हाल ही एफएमसीजी कंपनी नेस्ले के बेबी फूड में अतिरिक्त चीनी मिलने की रिपोर्ट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह रुख अपनाया है।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बैंच ने कहा, 'भ्रामक विज्ञापन का मुद्दा पतंजली तक सीमित नहीं है, यह उन सभी एफएमसीजी(फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स) कंपनियों तक है, जो धोखा दे रही हैं और इससे शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर हो रहा है।' सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मामले, सूचना व प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा है कि उन्होंने उपभोक्ता कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या किया। *(दै.भा., 24.04 24)*

# किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब हैं विकसित भारत का मजबूत स्तंभ

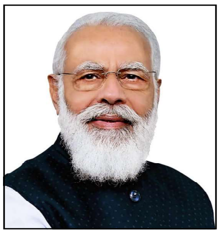

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने वहां किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त जारी कर किसानों के खाते में करीब 20 हजार करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

उन्होंने मेहदीगंज में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई अनाज होना चाहिए। आने वाले समय में मोटे अनाज की पैदावार और औषधीय गुणों वाले खाद्यान्न पर हमारा फोकस होगा। हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मोदी ने कहा मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत भी इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों के जुड़ा किया गया है। देशभर में गरीब परिवारों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने हों या सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों लोगों को सशक्त करेंगे। *(रा.प. एवं दै.भा., 19.06.24)*

## देश में बढ़ी नौकरीपेशा लोगों की संख्या

भारत ने रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नौकरीपेशा लोगों की संख्या लगभग 5 फीसदी बढ़कर 58 करोड़ हो गई है। आरबीआई के 'केएलईएमएस' डेटाबेस के मुताबिक 2021-22 में नौकरी करने वालों की संख्या 55.3 करोड़ थी।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 साल में करीब 11 करोड़ नौकरियां बढ़ी है। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में देश में नौकरी करने वालों की संख्या करीब 47.1 करोड़ थी और अब करीब 58 करोड़ पहुंच गई है। गौर तलब है कि आरबीआइ का केएलईएमएस डेटा, उत्पादन में पांच इनपुट पूंजी (के), श्रम(एल), ऊर्जा(ई), सामग्री (एम) और सेवाओं (एस) के बारे में जानकारी प्रदान करता है। *(रा.प., 03.05.24)*

## भारत बदल रहा और आगे बढ़ रहा है

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संसद द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में किए बदलाव इस बात का साफ संकेत है कि भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नए कानूनों को समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है।

'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' विषय पर दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह नए कानून तभी सफल होंगे जब हम नागरिक के तौर पर उन्हें अपनाएं। नए कानून ने क्रिमिनल जस्टिस पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग मे बदल दिया है।

पीड़ितों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपराध की जांच व अभियोजन कुशल तरीके से हो इसके लिए जरूरी बदलाव व सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा त्वरित सुनवाई के लक्ष्य को साकार करने के लिए अदालतों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है, अन्यथा समय सीमाओं का कोई फायदा नहीं होगा। *(रा.प., 21.04.2024)*

## गरीबों के लिए बनेंगे 3 करोड़ घर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए तीन करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय आम चुनाव के बाद बनी नई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया है।

गौरतलब है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इसके तहत अब तक 4.21 करोड़ आवास निर्मित हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को घर निर्मित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत बने आवासों में बिजली, पानी, शौचालय तथा एलपीजी जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है। *(रा.प., 11.06.24)*

## आधार से लिंक होगी किसानों की जमीन

केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के तहत राज्य के करीब एक करोड़ किसानों की जमीनों को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 582.61 लाख रुपए का बजट मंजूर करते हुए 45.72 लाख रुपए जारी कर दिए हैं।

इसके लिए राजस्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। सूचना एवं संचार विभाग आधार से लिंक किए जाने की अनुमति देगा। इसके बाद ऑनलाइन जमाबंदी से जुड़े सॉफ्टवेयर में आधार लिंक किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। जमाबंदी से आधार लिंक करने के लिए पटवारियों व ई-मित्र की सेवाएं ली जाएगी। *(दै.भा., 03.05.24)*

## प्रदेश में लगाए जाएंगे 7 करोड़ पौधे

पर्यावरण संरक्षण को नई गति देने के लिए प्रदेश में 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान' शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सात करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3 करोड़ पौधे आमजन को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इनमें से 3 करोड़ पौधे राजकीय भूमि और एक करोड़ पौधे ओरण एवं चरागाह भूमि पर लगाए जाने हैं। पेड़ पौधों की भूमिका पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अमूमन हरियाली बढ़ाने के नाम पर खानापूर्ति सामने आती रही है।

समूचे राजस्थान में गर्मी के प्रकोप का कारण भी यही है। गांवों से लेकर शहरों तक अवैध कटाई से हरियाली चौपट हो गई है। जहां भी पौधारोपण हो वहां पौधों की सार-संभाल आवश्यक है, नहीं तो अकसर बहुत से पौधे पेड़ बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं।

*(दै.भा., 06.06.24 एवं रा.प. 07.06.24)*

### प्रदेश में लगेंगे चार सोलर प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बनने वाले चार सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीकानेर जिले के पूगल एवं छत्तरगढ़ तहसील में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापित होंगे। वहीं फलौदी के भड़ला में 500 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होगा।

उक्त परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही एमएनआरई अनुमोदित परियोजना होने से इनपर 33 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। मानना है कि इन परियोजनाओं से सालाना 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे और पर्यावरण का संरक्षण होगा। सोलर पार्क में अत्याधुनिक सौर पैनल्स और ग्रिड टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा।

*(रा.प. एवं दै.भा., 17.06.24)*

### सोलर पैनल निर्माण में होंगे आत्मनिर्भर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल की गुणवत्ता, स्वदेशी उत्पादन एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए एएलएमएम नोटिफिकेशन, जो कि इन सभी मानकों को सुनिश्चित करता है, उसको एक अप्रैल से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है।

सोलर पावर संयंत्र को स्थापित करने के लिए व सोलर पैनल का उपयोग करने के लिए 25 साल की वारंटी जरूरी होती है। अतः यह आवश्यक है कि सोलर पैनल का उत्पादन अपने देश में ही सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं निर्माण की विश्वसनियता को आवश्यक रूप से कायम किया जाए। भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से देश में सोलर पैनल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। *(दै.भा., 02.04.24)*

### महंगी बिजली खरीद, चुका रहे उधारी

केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को बार बार चेताया जा रहा है कि वे आगामी वर्षों के लिए बिजली डिमांड का आकलन कर अपने पावर प्लांटों से उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। जरूरत के अनुरूप पावर परचेज एग्रीमेंट भी करें, ताकि बिजली कटौती की नौबत नहीं आए।

राजस्थान इसे नजरअंदाज करता रहा है। इसकी वजह वर्तमान में बिजली संकट पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की खामियों का बड़ा साइड इफेक्ट है। अभी बिजली संकट के समय पूर्व में दूसरे राज्यों से ली गई उधारी, 900 मेगावाट बिजली उन्हें लौटानी पड़ रही है। इसके लिए एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है।

पूर्ववर्ती उधार 34,800 लाख यूनिट बिजली में से अभी तक 13,200 लाख यूनिट बिजली लौटाई गई है। अभी भी 21,600 लाख यूनिट बिजली लौटानी बाकी है। राज्य सरकार ने इस स्थिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी है।

*(रा.प., 25.05.24)*

### बिजली बिल ने बिगाड़ा घर का बजट

इस बार 50 दिन भीषण गर्मी और लू का लंबा दौर चला है। हाल यह रहा कि करीब 20 से 22 दिन तक तो पारा 45 डिग्री पर भी रहा। ऐसे में जहां उपभोक्ताओं को गर्मी ने तपाने के साथ पसीने-पसीने किया, वहीं अब बिजली के भारी भरकम बिल ने उनके घर का बजट बिगाड़ दिया है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि जून के महीने में मिला बिजली बिल पिछले औसत बिल की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा है। डिस्कॉम के अनुसार भीषण गर्मी के दौर में कूलर, पंखे, एयरकंडीशनर और फ्रिज जैसे बिजली उपकरणों के चलने का समय बढ़ने से उपभोग बढ़ा है इससे बिल की राशि बढ़ी है। उपभोक्ताओं के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सब्सिडी योजना भी सियासत में उलझी है। इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है।

*(रा.प., 11.06.24, 21.06.24)*

### बिजली का लेन-देन होगा बंद

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से चली आ रही दूसरे राज्यों से बिजली की लेन-देन (बैंकिंग) अब राजस्थान सरकार नहीं करेगी। इससे अप्रैल से जुलाई के भीषण गर्मी वाले महीनों में लगभग 22,400 लाख यूनिट बिजली जो दूसरे राज्यों को लौटानी पड़ती थी वो नहीं लौटानी पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में सर्दियों में रबी फसल के लिए बिजली की अतिरिक्त जरूरत होती है। ऐसे में अक्टूबर से फरवरी के बीच दूसरे राज्यों से बिजली ली जाती थी। इसे मार्च से सितंबर के बीच लौटाना होता है। इस संकट से निपटने के लिए 18000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए एमओयू, कांट्रेक्ट किए गए हैं। अब 3 थर्मल प्लांट कोटा, झालावाड़ और बारां में लगेंगे। इससे बिजली लेन-देन की आवश्यकता नहीं होगी। *(दै.भा., 12.06.24)*

### ग्रीन एनर्जी में क्षमता से आगे राजस्थान

सोलर और विंड एनर्जी के उत्पादन में प्रदेश अपनी क्षमता से भी आगे बढ़ गया है। हालत यह है कि जितनी क्षमता में हम बिजली बना रहे हैं उतनी क्षमता से ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में 400 केवी की लाइनों पर ही राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम का पूरा सिस्टम चल रहा है। यह लाइनें भी अब ओवरलोड होकर हांफने लगी है।

इससे कई बार ट्रिपिंग और सिस्टम लॉक होने की समस्या आती है। सरकार ने ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन को उच्च गुणवत्ता का बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए की लागत से 765 केवी जीएसएस की घोषणा की थी, लेकिन यह कागजों से बाहर नहीं आ पाया है। नतीजतन अभी जो पश्चिम राजस्थान में बिजली बन रही है वह पावरग्रिड के 765 केवी जीएसएस की लाइनों से जा रही हैं। अब प्रसारण निगम का जीएसएस बनने के बाद बिना लॉसेज के बिजली सीधे उत्तरी ग्रिड तक पहुंच पाएगी।

*(रा.प., 10.06.24)*

## प्रदेश के भूजल स्तर में हो रही गिरावट

प्रदेश में भूजल स्तर की लगातार गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। राज्य के 17 जिलों के 38 ब्लॉक, 1132 ग्राम पंचायत में गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम के लिए अटल भूजल योजना से काम होना है। लेकिन योजना के अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं।

प्रदेश में अटल भूजल योजना से कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्यानिकी विभाग व जलदाय विभाग को आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में कृषि व उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की प्लानिंग भी नहीं हो पा रही है। अटल भूजल योजना के माध्यम से जन सहभागिता से गिरते भूजल स्तर की रोकथाम और इसके सकारात्मक परिणाम लाने की जरूरत है। *(दै.भा., 05.05.24)*

## देश में जल संकट का गंभीर खतरा

कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में जुड़ी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2050 तक भारत के 50 से ज्यादा जिलों में पानी का विकट संकट हो सकता है। डीसीएम श्री राम और सत्व नॉलेज की एक रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2050 तक देश में प्रति व्यक्ति जल की मांग में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती आबादी व जल संसाधनों की कमी के चलते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में 15 प्रतिशत की कमी आ सकती है। इससे मांग और सप्लाई में कमी के चलते संतुलन बिगड़ने की संभावना है। अभी भी 75 फीसदी भारतीयों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल जल का 80 से 90 फीसदी हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। इसके बाद घरेलू व इंडस्ट्री क्षेत्र में जल का उपयोग होता है। मद्देनजर देश में कुशल सिंचाई के द्वारा जल बचाने की जरूरत है। *(दै.भा., 22.04.24)*

## सबसे ज्यादा डार्क जोन राजस्थान में

देश के 6533 ब्लॉकों में से 27 फीसदी में भूगर्भ जल काफी नीचे खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से अति शोषित क्षेत्र हैं। हालांकि यहां रिचार्ज के लिए जल उपलब्ध है।

दूसरी ओर, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से देश के अत्यधिक जल शोषण क्षेत्र में हैं। यहां सीमित मात्रा में वाटर रिचार्ज का विकल्प है। देश के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश और रिचार्ज की पहल करने से भूजल की स्थिति में सुधार हुआ है। देश में भूगर्भ जल की सबसे खराब हालत राजस्थान में है। यहां सबसे ज्यादा 203 क्षेत्र डार्क जोन में है। *(दै.भा., 08.06.24)*

## गांव के लोगों ने पेश की नजीर

राजसमंद जिले में घोड़ातलाई गांव के लोगों ने शहरों की ओर पलायन कर रहे परिवारों को रोक कर एक नई नजीर पेश की है। गांव में ज्यादातर भील समुदाय के लोग है, जिनकी आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं।

कुछ सालों से बारिश नहीं होने के कारण भूजल बहुत नीचे चला गया। कई परिवार पलायन करने लगे। इसे रोकने के लिए पंचायत ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और वर्षा के जल को रोकने की मुहिम चलाई। पलायन कर रहे लोगों को शहर जितने वेतन पर काम देना शुरू किया। उन्होंने पानी स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए। इसके लिए ग्रामीणों ने करीब चार लाख रुपए से ज्यादा का योगदान दिया। इससे पलायन रुकने के साथ ही गांव में ही रोजगार मिला और पानी की समस्या का भी समाधान हुआ। गांव में अब लोग वापस खेती व पशुपालन के काम में जुटे हैं। *(रा.प., 24.04.24)*

## गांवों में बनेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी एक बड़ी समस्या है। मौसम विभाग ने अच्छे मानसून की भविष्यवाणी करके एक खुशखबर दी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में प्रदेश के 20 हजार गांव-ढाणियों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, ताकि जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में आमजन को समुचित जल उपलब्ध कराने की दिशा में यह अभियान संजीवनी साबित होगा। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए जन साधारण की भागीदारी आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा हो। *(दै.भा., 04.06.24)*

## घर-घर नल कनेक्शन में प्रदेश पिछड़ा

देश में जल जीवन मिशन को शुरू हुए चार साल से अधिक समय हो गया है लेकिन राजस्थान अभी भी घर-घर नल कनेक्शन देने में पिछड़ा हुआ है। मिशन के तहत किए गए सर्वे के अनुसार प्रदेश में 50 फीसदी काम भी पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान में अब तक केवल 48.71 प्रतिशत घरों को नल से जल का कनेक्शन मिला है।

सर्वे के अनुसार प्रदेश में 1,06,99,260 घर नल कनेक्शन देने के लिए चिन्हिति किए गए। लेकिन अभी तक नल कनेक्शन 52,11,771 घरों को ही मिले है। अब केंद्र व राजस्थान में भाजपा की सरकार है। *(रा.प., 13.05.24)*

## जल जीवन मिशन में बढ़ेगी रफ्तार

प्रदेश में जल जीवन मिशन में अब तेजी से काम होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने हाल ही काम की रफ्तार बढ़ाने को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को काम में तेजी लाने और पिछली सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार, घोटालों की जांच और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी दो महीने में 19,152 करोड़ के वर्कआर्डर हो जाएंगे। इसके बाद जलजीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी। काम में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मिशन के तहत होने वाले कार्यों में पानी के स्रोत का पहले पता किया जाएं, ताकि जलापूर्ति में बाधा नहीं आए। प्रतिदिन हुए कामों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार अफसर अधिकृत हों। *(दै.भा., 10.06.24)*

### महिलाओं की बेरोजगारी दर घटी

देश में वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में महिलाओं की श्रम बल में हिस्सेदारी दर बढ़कर 6 साल के उच्चतम स्तर 25.6 प्रतिशत पर पहुंच गई है। हालांकि यह ग्रामीण इलाकों की तुलना में अभी भी कम है। शहरी इलाकों में नियमित वेतन पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है।

पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मार्च तिमाही 2024 के आकड़ों का विश्लेषण करने पर यह जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक इस दौरान स्वरोजगार यानी खुद का बिजनेस करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस अवधि में कुल कामकाजी महिलाओं में नियमित वेतन पर काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी घटकर 52.3 फीसदी रह गई, जो दिसंबर तिमाही, 2023 में 53 प्रतिशत थी। वहीं स्वरोजगार करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 41.3 प्रतिशत हो गई जो दिसंबर तिमाही में 40.3 प्रतिशत थी। *(रा.प., 20.05.24)*

### शिक्षक भर्ती में बढ़ेगा महिला आरक्षण

प्रदेश सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला किया है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 2.70 लाख से अधिक पद है। इनमें करीब 60 हजार पद खाली है। इन पर भर्ती होती है तो करीब 30 हजार पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके साथ ही राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। संशोधन के बाद 50 फीसदी आरक्षण लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार का फोकस महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ज्यादा है। इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। *(रा.प., 15.06.24)*

### जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव

भारत में महिलाएं और बच्चे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं से खासतौर पर असुरक्षित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रायोजित एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है। इसमें बाढ़, तूफान और सूखे जैसी आपदाओं का बच्चों और महिलाओं पर पड़ रहे असर का अध्ययन किया गया।

इस अध्ययन में यह सामने आया कि आपदाग्रस्त इलाकों के बच्चों में नाटा रह जाने, कम वजन होने के साथ प्रीटर्म बच्चे होने की आशंका ज्यादा रहती है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 183 जिले चक्रवात-बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील थे, जबकि 349 जिलों में सूखा पड़ा। भारत में करीब 51 फीसदी बच्चे गरीबी और जलवायु संकट की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। अध्ययन के अनुसार किसी भी प्रकार के जलवायु संकट का असर पोषण, तापमान, सफाई आदि के पैमानों पर बच्चों पर ही सबसे ज्यादा असर होता है। *(रा.प., 13.05.24)*

### बच्चे हो रहे हैं कुपोषण के शिकार

प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन अनेक योजनाओं और माध्यमों मसलन आंगनबाड़ी और स्कूलों में पोषाहार खिलाने, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व पोषाहार देने आदि पर हर साल हो रहे मोटे खर्चे के बावजूद धरातल पर सही परिणाम सामने नहीं आना चिंताजनक है।

राज्य में अब भी 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है। हाल ही जारी ताजा पोषण ट्रेकर रिपोर्ट इसका खुलासा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 12976 कुपोषित बच्चे उदयपुर में हैं, जिनमें 3483 बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में है। दूसरे स्थान पर दौसा जिला है जिसमें 12459 कुपोषित और 3477 बच्चे अति कुपोषित है। बांसवाड़ा 10063 कुपोषित व 3594 अतिकुपोषित बच्चों के साथ तीसरे स्थान पर है। अन्य जिलों में भी करीब-करीब ऐसी ही स्थिति है। *(दै.भा., 04.04.24)*

### महिलाओं को तापमान बीमा भुगतान

अत्यधिक गर्मी पर भारत में पहली बार करीब 50 हजार महिलाओं को तापमान बीमा (मौसमी आपदाओं पर कमजोरों की मदद) का भुगतान किया गया है। सभी महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। योजना के तहत यह भुगतान उन महिलाओं को किया जाता है, जिनका काम-काज गर्मी के कारण प्रभावित हुआ हो।

देश के कई शहरों में 18 से 25 मई के बीच तापमान $40^0$ से भी ज्यादा पर चला गया था। इसी की एवज में राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र की महिलाओं को 400 रुपए का भुगतान किया गया। गौरतलब है, यह योजना अंतरराष्ट्रीय संस्था क्लाइमेट रेजिलिएंस फॉर ऑल (सीआरए) ने भारत में महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था सेल्फ-इंप्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन (सेवा) के साथ मिलकर शुरू की है। सीआरए की सीईओ कैथी बॉगमन ने बताया कि पहली बार सीधे भुगतान को बीमा योजना के साथ जोड़ा है ताकि महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा सके। *(रा.प., 13.06.24)*

## कब मिलेगा 'आधी आबादी' को पूरा हक

आजादी के 76 साल बाद देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिनमें नारी शक्ति की भागीदारी का आंकड़ा मात्र 13.63 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया है। इस चुनाव में 74 महिला सांसद चुनी गई है, जिनमें 43 नए चेहरे हैं, जो पहली बार लोकसभा में अपनी भागीदारी निभाएंगी।

लोकसभा की 543 सीटों की संख्या के लिहाज से इस बार निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी मात्र 13.63 प्रतिशत है, जो 33 प्रतिशत हिस्सेदारी से काफी दूर है। पिछले कुछ सालों में इस दिशा में बातें तो खूब हुईं पर अमल में नहीं लाई जा सकी। हालांकि इस बार संसद में नारी वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) पारित हो चुका है। इससे उम्मीद बंधी है कि आने वाले वर्षों में राजनीति के हर स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। *(रा.प., 07.06.24)*



संगठन हमारी जान है! मिलकर हम तूफान हैं!!

## जयपुर ट्रैफिक पुलिस की पहल

जयपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के साथ अब ट्रैफिक पोल पर भी उसी रंग की लाइट दिखेगी, जिस रंग का सिग्नल होगा। ट्रैफिक पुलिस ने यह पहल करते हुए ट्रैफिक पोल एलीमिनेशन किया है। डीसीपी ट्रैफिक, सागर राना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शहर के प्रमुख चौराहे रामबाग पर ट्रायल के तौर पर यह पहल की गई है।

इसके बाद जेडीए सर्किल, नारायण सिंह सर्किल, गवर्नमेंट चौराहे, सीकर रोड़ के चौराहे के साथ-साथ जहां से भारी वाहन गुजरते हैं वहां ट्रैफिक पोल एलीमिनेशन किया जाएगा। जिससे वाहन चालकों को दूर से ही सिग्नल नजर आ जाएं। साथ ही भारी वाहनों के कारण भी छोटे वाहनों के चालकों को ट्रैफिक सिग्नल नजर नहीं आते, ऐसे में पोल एलीमिनेशन से उन्हें सिग्नल का पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि एलईडी लाइट में ही तीनों रंग लाल, पीला व हरा रंग है, जिसे सिग्नल लाइट से जोड़ा गया है।

*(दै.भा., 12.05.24)*

## एआई यातायात प्रबंधन होगा लागू

पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संचालित यातायात प्रबंधन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। राज्य परिवहन विभाग पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा है। इसका मकसद यातायात प्रबंधन को आधुनिक, स्मार्ट बनाना और साथ ही राज्य में यातायात नियमों का सटीक और कड़ाई से पालन करना है।

एआई संचालित यातायात प्रबंधन व्यवस्था से सड़क सुरक्षा बढ़ने के साथ ही अवैध, गैर कानूनी वाहनों को चलाना कठिन होगा। नियमों के उल्लंघन की तत्काल जानकारी मिलेगी और ए आई सिस्टम से तुरंत कार्रवाई भी होगी। इससे वाहनों की ओवरस्पीडिंग, गलत लेन का उपयोग और लाल बत्ती पर गाड़ी चलाना जैसे ट्रैफिक उल्लंघनों का तुरंत पता चल जाएगा। नई व्यवस्था के बारे में सरकारी वाहनों समेत सभी वाहन मालिकों को अपने दस्तावेज अपडेट करने के लिए सूचित किया गया है। *(दै.भा., 21.04.24)*

## फुटपाथ का मुद्दा ठंडे बस्ते में

वर्ष 2019 की ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में राजधानी जयपुर में फुटपाथ विकसित करने और मरम्मत को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद टीबीसी की बैठक में राहगीरों का यह मुद्दा ही गायब हो गया। इससे पैदल चलने वाले राहगीरों की डगर कठिन होती जा रही है।

हाल ही केंद्र सरकार के शहरी विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि राजधानी जयपुर में करीब 65 प्रतिशत फुटपाथ ही चलने लायक है। जबकि चंडीगढ़ में 90, दिल्ली में 88, अहमदाबाद और मुंबई में 85 फीसदी फुटपाथ चलने लायक है। इससे पहले जेडीए ने भी फुटपाथों का सर्वे करवाया था, उस रिपोर्ट में 50 फीसदी फुटपाथ ही ऐसे मिले जिन पर लोग आसानी से चल सकते हैं।

ऐसा लगता है जेडीए के लिए फुटपाथ महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि टूरिस्ट सिटी होने के कारण यहां पैदल चलने वाले राहगीरों की संख्या ज्यादा रहती है। गौरतलब है, सेंटर फॉर ग्रीन मॉबिलिटी ने जेडीए के साथ मिलकर टोंक रोड की एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें सड़क के दोनों ओर 3.5-3.5 मीटर के फुटपाथ बनाएं जाएं। इसमें फुटपाथ के साथ-साथ साइकिल ट्रैक भी प्रस्तावित था लेकिन 10 वर्ष से यह प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में बंद पड़ा है।

*(रा.प., 13.05.24)*

## सड़क हादसे रोकने का बनेगा प्लान

प्रदेश में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए 10 साल के लिए रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी एवं एक्शन प्लान प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। प्लान बनाने का निर्देश मुख्य सचिव डॉ. सुधांशु पंत ने शासन सचिवालय में आयोजित परिवहन अधिकारियों की बैठक में दिए।

इस दौरान प्लान के तैयार प्रारूप पर चर्चा के लिए मुख्य सचिव ने विभिन्न सड़क सुरक्षा हितधारक विभागों की बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा तथा आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा सहित, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा शिक्षा, एलएसजी, यूडीएच, रोडवेज, एनएचएआई, जेसीटीएसएल, मोटर गैराज, स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा, वन विभाग, एनआईसी, आरएसआरडीसी, आबकारी तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ये सभी अब सड़क हादसों को रोकने के लिए सुझाव देंगे। *(दै.भा., 07.06.24)*

---

# 'मैप माय इंडिया' पर ब्रेकर, स्पीड, कैमरों की लोकेशन...

यातायात पुलिस द्वारा सुगम यातायात सुविधा के लिए 'मैप माय इंडिया' के साथ किए गए एमओयू के तहत एप पर शहर के 20 ब्लैक स्पॉट की फोटो लोकेशन अपलोड करवाने के बाद स्पीड ब्रेकर, एरिया स्पीड लिमिट व स्पीड कैमरों की लोकेशन भी अपलोड करने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अलावा इस एप पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले डायवर्जन की जानकारी भी तय समय पर अपलोड की जाएगी।

डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि मैप माय इंडिया के साथ 11 जून को एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत प्रथम फैज में शहर के 20 ब्लैक स्पॉट की फोटो और जानकारी अपलोड करवा दी गई। अब इस एप पर शहर के सभी मेजर स्पीड ब्रेकर व पुलिस की तरफ से लगे स्पीड केमरों की लोकेशन भी अपलोड की जाएगी, ताकि ब्रेकर व कैमरा नजदीक आने पर चालक सावधान हो जाए।

इसके साथ ही मैप पर एरिया वाइज स्पीड लिमिट की जानकारी दी जाएगी। डीसीपी राणा ने बताया कि अगर सड़क पर अचानक कोई हादसा हो जाए तो आमजन भी फोटो खींच कर जानकारी भेज सकेंगे। ये जानकारी पहले पुलिस के पास जाएगी। जिसकी तुरंत तस्दीक करवाकर मैप पर अपलोड करवाएंगे। *(दै.भा., 17.06.24)*

**उपभोक्ता फैसले**

### दिव्यांग को डिफेक्टिव डी-फ्रीज बेचना पड़ा भारी

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में किशनगढ़ निवासी दिव्यांग ओम प्रकाश कुमावत ने परिवाद दायर कर बताया कि पूरी तरह दिव्यांग होने पर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसे जीविकोपार्जन के लिए किशनगढ़-रेनवाल बस स्टैंड लाखेरा पर सरस डेयरी बूथ आवंटित किया था। डेयरी बूथ में दूध, दही, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसने डी-फ्रीज खरीदा था, लेकिन वह डिफेक्टिव निकला। मामले की खुद पैरवी करते हुए उसने आयोग को मामले की सारी जानकारी दी।

सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने ओम प्रकाश कुमावत के पक्ष मे फैसला देते हुए डिफेक्टिव डी-फ्रीज बेचने को अनुचित व्यापार प्रथा करार दिया। आयोग ने विपक्षी पार्टियों डी-फ्रीज विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 2.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षियों को निर्देश दिया है कि वे डी-फ्रीज की कीमत 29,500 रुपए भी परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित ओम प्रकाश कुमावत को अदा करें। *(दै.भा., 13.05.24)*

### इलाज में कोताही, मिलिट्री अस्पताल देगा जुर्माना

राज्य उपभोक्ता आयोग, जोधपुर में सारण नगर निवासी पूर्व सैनिक ज्ञान प्रकाश चौहान ने मिलिट्री हॉस्पिटल, वहां के दो डॉक्टर, दिल्ली स्थित कमांडेंट बेस हॉस्पिटल व सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के खिलाफ परिवाद दर्ज कराकर बताया कि उनकी पत्नी सरिता कंवर को अप्रेल 2007 में मिलिट्री अस्पताल में भर्ती किया। इसके बाद चिकित्सकों की लापरवाही से उनकी पत्नी को कार्डियक अरेस्ट और हाईपोक्सिक ब्रेन डेमेज हो गया। इससे वह कोमा में चली गई। उनकी संतान की मृत्यु गर्भ में पहले ही हो गई। इसके बाद पत्नी सरिता की मार्च 2009 में मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई पर अस्पताल की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि सावधानी से इलाज करने के बाद बीमारी से मौत हुई है। उपभोक्ता राज्य आयोग ने मिलिट्री हॉस्पिटल, इसके दो डॉक्टर, दिल्ली स्थित कमांडेंट बेस हॉस्पिटल व सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को आदेश दिया कि वे 45 दिन में एक मुश्त 10 लाख रुपए तथा 25 हजार रुपए परिवाद खर्च के अलग से परिवादी पूर्व सैनिक ज्ञान प्रकाश चौहान को अदा करें। *(रा.प. एवं दै.भा., 04.06.24)*

### वकील उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे से बाहर-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वकीलों पर सेवा में 'खामी' के लिए उपभोक्ता अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता। वकील उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने एक अपील पर यह फैसला सुनाया, जिसमें सवाल उठाया था कि क्या सेवाओं में कमी के लिए वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

फैसले में कहा कि वकीलों की सेवा अलग तरह की है। उपभोक्ता संरक्षण कानून से उन्हें बाहर रखना चाहिए। उक्त फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कंज्यूमर कमीशन का 2007 का वह फैसला रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उपभोक्ता अधिकारों का ध्यान रखते हुए अगर वकील ठीक से सेवा नहीं देते हैं तो उन्हें उपभोक्ता अदालत में लाया जा सकता है।

पीठ ने फैसले में यह भी कहा कि फीस देकर कोई काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की 'सेवा' के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अगर वकील गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है। *(रा.प., 15.05.24)*

## स्वच्छ जयपुर, हरित जयपुर अभियान शुरू - लोगों को भी कर रहे जागरूक

जयपुर स्थित सेंट्रल पार्क को साफ सुथरा और हरा भरा रखने के लिए 'कट्स' इंटरनेशनल की ओर से स्वच्छ जयपुर, हरित जयपुर अभियान की शुरुआत की गई है। पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इसका पोस्टर जारी किया। पार्क में कई जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं। अभियान के तहत पार्क में घूमने आने वाले लोगों को कूडा-कचरा नहीं फैलाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि जयपुर शहर को स्वच्छ और हराभरा बनाया जा सके।

'कट्स' इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप महता और सहयोगी शिवेंद्र शेखावत सैर के साथ ट्रैक और उसके आस-पास पड़े कचरे को उठा रहे हैं। अन्य लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि सेहतमंद रहने के लिए पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। संस्था का प्रयास है कि सभी मिलकर जयपुर को स्वच्छ और हरित बनाएं। 'कट्स' के इस अभियान से काफी लोग जुड़ भी रहे हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक करने में जुटे हैं।

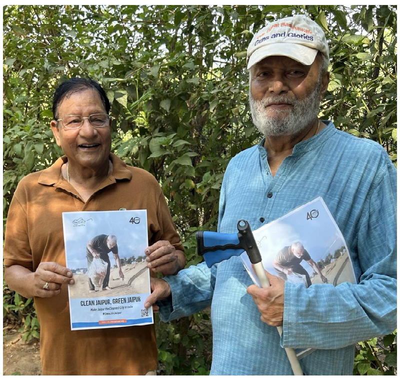


**स्रोतः** रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

**पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी**, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)